आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 32 (प्रति रविवार) इंदौर, 28 अप्रैल से 04 मई 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

देश की तरक्की कांग्रेस को अच्छी नहीं लगाती -मोदी

बेलगावी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। रविवार को कर्नाटक में पीएम मोदी की चार चुनावी रैलियां है। सबसे पहले बेलगावी में उन्होंने रैली को संबोधित कर कहा कि 'कर्नाटक के सभी वोटर का अभिनंदन कर्नाटक में जहां-जहां गया सिर्फ एक स्वर सुनाई देता है फिर एकबार मोदी सरकार।

उन्होंने कहा ईवीएम के बहाने कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की। 10 साल में भारत और शक्तिशाली हुआ भारत की पहचान लोकतंत्र के मां के रूप में होने लगी है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। भारत जब आगे बढ़ता हैं, तब हर भारतवासी को गर्व होता है। कांग्रेस देशहित से इतनी दूर हो गई है, परिवार हित में इतना खो चुकी है कि देश की तरक्की अच्छी नहीं लगती। भारत की हर सफलता पर कांग्रेस को शर्म आने लगी है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे पाप को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका राजपूतों पर जो बयान दिया आप सभी ने सुना होगा। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवराज, चिन्नमा महारानी जैसे महान लोगों का अपमान किया, जिनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। यह सोच समझकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दिया गया बयान है। राजा महाराज को बुरा कह दिया लेकिन बादशाहों, सुल्तान के अत्याचारों पर शहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है । प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन्होनें हमारे मंदिरों को तोड़ा अपमान किया वे उस औरंगेजब के गुणगान करने वालों के साथ हाथ मिलाते हैं। गौ हत्या, लूटपाट करने वाले नवाब शहजादे को वे याद नहीं आए जिन्होने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। यहां बेलगावी में एक बहन के साथ जो हुआ और जैन मुनि के साथ जो हुआ शर्मसार करने वाला है। हुगली में हमारी एक बेटी के साथ जो हुआ उस घटना ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। बैंगलुरू के कैफे में बम धमका हुआ, तब उस भी गंभीरता से नहीं लिया गया।

ओडिशा में भाजपा-बीजद की शादी हो चुकी-राहुल

ओडिशा (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को ओडिशा पहुंचे। उन्होंने केंद्रपाड़ा में रैली में कहा- ओडिशा में भाजपा-बीजदकी शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल% और नवीन बाबू ने इस शादी में ओडिशा की जनता को पान दिया है। पान मतलब... पीए पांडियन (नवीन पटनायक के करीबी आईएएस अफसर)- अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक इन्होंने मिलकर आपका पैसा लूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच गठबंधन है। पीएम मोदी ने केंद्र में 22-25 अरबपतियों की सरकार चलाई। वही काम ओडिशा में नवीन बाबू कर रहे हैं।

राहुल ने कहा- इसका पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों को होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। तेलंगाना में भाजपा और ~~क्क्र~~ की शादी थी। वहां पर हर रोज उनकी बारात निकलती थी और ड्रामेबाजी होती थी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दिखाया कि भाजपा और यूबीआरएस एक हैं और अगर विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ओडिशा में भी कुछ यही हाल है।

ओडिशा के लिए 5 गारंटी गिनाई-राहुल गांधी ने ओडिशा के लिए पांच गारंटी गिनाई। उन्होंने कहा-

ओडिशा में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और धान के लिए 3,000 रुपए क्विंटल।

युवा न्याय-पहली नौकरी पक्की- हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार।

भर्ती भरोसा- 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे।

पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां

गग-वर्कर सुरक्षा- गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा।

युवा रोशनी- युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड।

कांग्रेस-बीजेपी एक, इन्होंने बसपा को तोड़ा-मायावती

मुरैना (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को एक बताया। कहा कि उत्तरप्रदेश में चार बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी। जब चौथी बार अकेले बलबूते हमारी सरकारी बनी, तब कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी जातिवादी पार्टियों ने एक होकर बीएसपी को कमजोर करने के लिए रास्ता निकाला। इन्होंने स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों को तोड़ा। इन्हें आगे कर छोटे संगठन बनवा दिए और बीएसपी के मुकाबले में ले आए। मायावती ने कहा, ग्वालियर में भी एक-दो ऐसे स्वार्थी और बिकाऊ लोग हैं, जिहोंने कांग्रेस और बीजेपी का मकसद पूरा किया। जब लगा कि बीएसपी कमजोर हो गई, तब कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये बात बाबा साहेब की करते हैं, काम गांधी जी का करते हैं। इनसे सावधान रहना है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, ये बीमारी उत्तरप्रदेश में भी है। जहां बीएसपी मजबूत है, वहां विरोधी पार्टियां इस तरह का षड्यंत्र रच रही हैं। मायावती ने मुरैना शहर के मेला मैदान में रविवार को ग्वालियर, मुरैना और भिंड लोकसभा से बसपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। इससे पहले 19 अप्रैल को उन्होंने रीवा में सभा की थी।

गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर

मायावती ने कहा- आजादी के बाद केंद्र और देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता कांग्रेस के हाथ में केंद्रित रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग विरोधी गलत नीति और कार्यप्रणाली की वजह से कांग्रेस को केंद्र और काफी राज्यों की सत्ता से भी बाहर होना पड़ा है।

राहुल गांधी के जातिगत आरक्षण खत्म करने के आरोपों पर गरमाई राजनीति

शाह- भागवत, बोले- गुमराह करने की कोशिश, देश में कभी खत्म नहीं होगा आरक्षण

अहमदाबाद/गुजरात(एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के दो चरण खत्म होने के बाद अचानक आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जातिगत आरक्षण को लेकर दिए बयान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रदेशों में भी स्थानीय नेताओं ने राहुल के आरोप को निराधार बताया है।

गौरतलब है, राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर कहा था कि भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदल कर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीन कर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। अमित शाह ने पलटवार कर कहा कि राहुल गांधी निराधार

झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और दो बार पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है। अगर भाजपा की मंशा आरक्षण को खत्म करने की होती तो अब तक हो चुकी होती। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई-बहनों को ये गारंटी दी है कि जब तक भाजपा है तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता।

शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमला किया है। कर्नाटक में उनकी सरकार आई और चार प्रतिशत अल्पसंख्यक आरक्षण बनाया, किसका कोटा काट दिया गया? ओबीसी (आरक्षण) में कटौती की गई। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां भी उन्होंने पांच प्रतिशत अल्पसंख्यक आरक्षण किया। किसका कोटा काट दिया गया? ओबीसी (आरक्षण) में कटौती की गई। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े समाज का विरोध किया और आदिवासियों को न्याय दिलाने का काम कभी नहीं किया।

आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में :भागवत

वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है, आरक्षण जारी रहना चाहिए। भागवत ने यह बात भाजपा और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर चल रहे बयानों के बाद कही। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि जब मैं यहां आया तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। हम इस बारे में बाहर बात नहीं कर सकते। अब यह पूरी तरह से झूठ है।

संपादकीय

साल गुजरा पर शांत नहीं हुआ मणिपुर

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान हिंसा हुई। मतदान के बाद भी हिंसा जारी है। मतदान खत्म होने के 6 घंटे बाद ही कुकी उग्रवादियों ने रात करीब 12 बजे मोइरंग थाने के नारायण सेना गांव में सीआरपीएफ की 128 बटालियन के शिविर पर हमला कर दिया। ढाई घंटे तक आमने-सामने की मुठभेड़ होती रही। सीआरपीएफ के चार जवान घायल हुए। दो जवानों की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। दो जवान घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इस मुठभेड़ में तीन उग्रवादी भी घायल हुए। मणिपुर में अभी तक सुरक्षा बलों के 12 से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं। दोनों ही पक्षों के उग्रवादियों ने दर्जनों थाने के हथियार लूट लिए। केंद्र राज्य सरकार के प्रयास के बाद भी अभी तक यहां पर शांति स्थापित नहीं हो पाई। पिछले चार दशक में मणिपुर राष्ट्रीय विचारधारा से पूरी तरह जुड़ चुका था। राजनीति के चलते कुकी और मैतई समुदाय के बीच में आरक्षण को लेकर सुनियोजित ढंग से अलगाववाद को बढ़ाया गया। राज्य सरकार और हाईकोर्ट के एक आदेश से सीमावर्ती राज्य मणिपुर पूरी तरह से न केवल अशांत हुआ, वरन प्रशासनिक संरक्षण के चलते कुकी समुदाय के सैकड़ों चर्च तोड़ दिए गए। महिलाओं की नंगी परेड निकाली गई। ईसाई और हिंदू धार्मिक ध्रुवीकरण का मणिपुर में जो खेल शुरू हुआ, वह तमाम कोशिशों के बाद भी शांत नहीं हो पा रहा है। कुकी और मैतई समुदाय के सेकड़ों लोगों की मौत हिंसक वारदातों में हो चुकी है। हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में पिछले कई महीनों से रह रहे हैं। मणिपुर दो भागों में बट चुका है। कुकी और मेतई एक दूसरे के इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री वीरेन सिंह की अगुवाई में अलगाववाद का जो खेल खेला गया था, वह और मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेन सिंह दोनों ही बने हुए हैं। मुख्यमंत्री को लेकर दोनों पक्षों में नाराजगी है। दोनों पक्षों में शासन और प्रशासन का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेतई समुदाय मुख्यमंत्री वीरेन सिंह से नाराज है। उन्होंने जो वायदे मैतई समुदाय से किए थे, वह उन्होंने पूरे नहीं किये। कुकी समुदाय और मेतई समुदाय के बीच हिंसा का वातावरण बनने से, दोनों ही समुदायों के लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से परेशान हैं। इसका हल केंद्र सरकार नहीं निकाल पाई है। राज्य सरकार पर दोनों ही समुदायों को भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कुछ निर्देश दिए थे, लेकिन उनका पालन भी मणिपुर की सरकार नहीं कर रही है। इस कारण मणिपुर की अशांति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही समुदायों का वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रशासनिक मशीनरी पर भरोसा नहीं रहा। प्रशासन नाम की कोई चीज मणिपुर में देखने को नहीं मिल रही है। मेतई समुदाय के इलाके में कुकी समुदाय के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नौकरी करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। इसी तरीके से मेतई समुदाय के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कुकी इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं। इतने समय के बाद भी दोनों ही समुदाय के हजारों, शरणार्थी शिवरों में रहने के लिए बाध्य हैं। छोटे-छोटे बच्चे और महिलाएं शरणार्थी शिविरों में नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। स्कूल बंद है, कारोबार बंद है। पहली बार किसी राज्य में इस तरह की अशांत स्थिति इतने लंबे समय तक बनी रही है। लोग अपने ही राज्य में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सीमावर्ती राज्यों को लेकर जिस तरीके की उपेक्षा केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। यह चिंता की बात है। जल्द से जल्द और समय रहते मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए सुनियोजित और समग्र प्रयास नहीं किए गए, तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार को लेकर जो विश्वास पिछले 50 सालों में बना था, वह विश्वास टूटते देर नहीं लगेगी। भारत सरकार और भारत की न्यायपालिका को स्वयं संज्ञान लेकर मणिपुर के दोनों वर्गों के नागरिकों के बीच विश्वास कायम करने के लिए आगे आना होगा। यह विश्वास तभी कायम होगा जब वर्तमान मुख्यमंत्री वीरेन सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर केंद्र सरकार मणिपुर को अपने नियंत्रण में ले। दोनों ही समुदाय का भरोसा शासन और प्रशासन पर बनाना होगा। बिना किसी राजनीति के कुकी और मेतई के बीच में समन्वय बनाने का प्रयास किए जाने पर ही मणिपुर शांत होगा। इसमें अब और विलंब किया गया तो इसके परिणाम बड़े घातक साबित हो सकते हैं।

दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है गंभीर चुनौती

ललित गर्ग

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकसभा चुनाव 2024 अनेक दृष्टियों से यादगार, चर्चित, आक्रामक एवं ऐतिहासिक होने के साथ-साथ अब तक का सबसे महंगा एवं दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार का चुनावी खर्च एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये के खर्च के साथ दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के खर्च की तुलना में इस बार दुगुना खर्च होगा। चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक महंगी एवं धन के वर्चस्व वाली होने से राजनीतिक मूल्यों का विसंगतिपूर्ण एवं लोकतंत्र की आत्मा का हनन होना स्वाभाविक है। चुनाव जनतंत्र की जीवनी शक्ति है। यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है। जनतंत्र के स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव की स्वस्थता, पारदर्शिता, मितव्ययता और उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनाव की प्रक्रिया गलत होने पर लोकतंत्र की जड़े खोखली होती चली जाती हैं। करोड़ों रुपए का खर्चीला चुनाव, अच्छे लोगों के लिये जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता बन्द करता है और धनबल एवं धंधेबाजों के लिये रास्ता खोलता है। इन चुनावों में अर्थ का अनुचित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण खर्च का प्रवाह जहां चिन्ता का कारण बन रहा है, वहीं समूची लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित करने का सबब भी बन रहा है। इस तरह की बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलियां डालना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके विरोध में व्यापक जनचेतना को जगाना जरूरी है। यह समस्या या विकृति किसी एक देश की नहीं, बल्कि दुनिया के समूचे लोकतांत्रिक राष्ट्रों की समस्या है।

18वीं लोकसभा चुनाव में हर राजनैतिक दल अपने स्वार्थ की बात सोच रहा है तथा येन-केन-प्रकारेण ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने की अनैतिक तरकीबें निकाल रहा है। एक-एक प्रत्याशी चुनाव का प्रचार-प्रसार करने में करोड़ों रुपयों का व्यय करता है। यह धन उसे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, राजनीतिक दलों एवं प्रायोजकों से मिलता है। चुनाव जीतने के बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसी कारण सरकार उनके अनुचित दबाव के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाती और अनैतिकता एवं आर्थिक अपराध की परम्परा को सिंचन मिलता रहता है। यथार्थ में देखा जाए तो जनतंत्र अर्थतंत्र बनकर रह जाता है, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। लेकिन इस तरह लोकतंत्र की आत्मा का ही हनन होता है, इस सबसे उन्नत एवं आदर्श शासन प्रणाली पर अनेक प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं।

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर चुनाव अभियान के लिए धन अलग-अलग स्रोतों से अलग-अलग तरीको से उम्मीदरवारों और राजनीतिक दलों के पास आता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए मुख्य रूप से रियल इस्टेट, खनन, कारपोरेट, उद्योग, व्यापार, ठेकेदार, चिटफण्ड कंपनियां, ट्रांसपोर्टर, परिवहन ठेकेदार, शिक्षा उद्यमकर्ता, एनआआई, फिल्म, दूरसंचार जैसे प्रमुख स्रोत है। इस साल डिजिटल मीडिया द्वारा प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दल पेशेवर एजेंसिया की सेवाएं ले रहे हैं। इनसे सबसे अधिक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान, रैली, यात्रा खर्च के साथ-साथ सीधे तौर पर गोपनीय रूप से मतदाताओं को सीधे नकदी, शराब, उपहारों का वितरण भी शामिल है। देश में 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में 2024 में 500 गुणा अधिक खर्च होने का अनुमान है। प्रति मतदाता 6 पैसे से बढ़कर आज 52 रुपये खर्च होने का अनुमान है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में होने वाले वास्तविक खर्च और अधिकारिक तौर पर दिखाए गए खर्चे में काफी अंतर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 32 राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों द्वारा आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2,994 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया। इनमें दिखाया गया कि राजनीतिक दलों ने 529 करोड़ रुपये उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन आयोग में पेश खर्च का ब्यौरा और वास्तविक खर्च के साथ-साथ उम्मीदवारों द्वारा अपने स्तर पर किए जा रहे खर्चे में काफी अंतर है। अमेरिकी चुनाव पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के रिपोर्ट का हवाला देते हुए, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने कहा कि यह 2020 के अमेरिकी चुनावों पर हुए खर्च के लगभग बराबर है, जो 14.4 बिलियन डॉलर यानी 1 लाख 20 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित होगा।

भारत में होने वाले चुनाव में हो रहे बेसुमार खर्च की तपीश समूची दुनिया तक पहुंच रही है। समूची दुनिया के तमाम देशों में भारत के चुनाव को न केवल दम साध कर देखा जा रहा है बल्कि इन चुनाव के खर्चों एवं लगातार महंगे होते चुनाव की चर्चा भी पूरी दुनिया में व्याप्त है। लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों एवं उनके उम्मीदावारों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये तिजोरियां खोल दी है। यह चुनाव राष्ट्रीय मसलों के मुकाबले राजनीतिक दलों के हित सुरक्षित रखने के वादे पर ज्यादा केंद्रित लग रहा है और टकराव के मुद्दे थोड़े ज्यादा तीखे हैं। लेकिन अगर मुद्दों से इतर अभियानों की बात करें तो यह खबर ज्यादा ध्यान खींच रही है कि इस बार चुनाव अब तक के इतिहास में सबसे खर्चीला साबित होने जा रहा है। इस चुनावों के अत्यधिक खर्चीले होने का असर व्यापक होगा। चुनाव के तवे को गर्म करके अपनी रोटियां सेंकने की तैयारी में प्रत्याशी वह सब कुछ कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करता है। काफी लंबे और जटिल प्रक्रिया के तहत चलने वाले चुनाव में जनता के बीच समर्थन जुटाने के लिए उम्मीदरवार जितने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हैं, उसमें उन्हें स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर सामग्रियों और जनसंपर्कों तक के मामले में कई स्तरों पर खर्च चुकाने पड़ते हैं। यों किसी भी देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले चुनावों में ऐसा ही होता है, लेकिन भारत में इसी कसौटी पर खर्च में कई गुना ज्यादा होना चिन्ता का सबब बनना चाहिए।

दुनिया की आर्थिक बदहाली एवं युद्ध की विभीषिका से चौपट काम-धंधों एवं जीवन संकट में लोकसभा के चुनाव कहां कोई आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जो लोग चुनाव जीतने के लिए इतना अधिक खर्च कर सकते हैं तो वे जीतने के बाद क्या करेंगे, पहले अपनी जेब को भरेंगे, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बनायेंगे। और मुख्य बात तो यह है कि यह सब पैसा आता कहां से है? कौन देता है इतने रुपये? धनाढ्य अपनी तिजोरियां तो खोलते ही है, कई कम्पनियां हैं जो इन सभी चुनावी दलों एवं उम्मीदवारों को पैसे देती है, चंदे के रूप में। चन्दा के नाम पर यदि किसी बड़ी कम्पनी ने धन दिया है तो वह सरकार की नीतियों में हेरफेर करवा कर लगाये गये धन से कई गुणा वसूल लेती है। इसीलिये वर्तमान देश की राजनीति में धनबल का प्रयोग चुनाव में बड़ी चुनौती है। सभी दल पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के समाधान के नाम पर नहीं। कोई भी ईमानदारी और सेवाभाव के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। राजनीति के खिलाड़ी सत्ता की दौड़ में इतने व्यस्त है कि उनके लिए विकास, जनसेवा, सुरक्षा, महामारियां, युद्ध, आतंकवाद की बात करना व्यर्थ हो गया है। सभी पार्टियां जनता को गुमराह करती नजर आती है। सभी पार्टियां नोट के बदले वोट चाहती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है। सभी जीवन मूल्य बिखर गए है, धन तथा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का अर्जन सर्वोच्च लक्ष्य बन गया है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि यह चुनाव आर्थिक विषमता की खाई को पाटने की बजाय बढ़ाने वाले साबित होने जा रहे हैं। आखिर कब तक चुनाव इस तरह की विसंगतियों पर सवार होता रहेगा?

एआईसीटीएसएल की बस सेवा योजना ठंडे बस्ते में

3 महीने बाद भी नहीं चल सकी इंदौर से अयोध्या के लिए बस

इंदौर। *एआईसीटीएसएल की इंदौर से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा फिलहाल ठंडे बस्ते में नजर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी में किया, तभी एआईसीटीएसएल की योजना रही कि इंदौर से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाए। इससे लोगों को भगवान श्रीराम के दर्शन करने के लिए सुविधा हो। हालांकि करीब 3 महीने बाद भी इस योजना को अमलीजामा नहीं पहनाया जा पाया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते इंदौर के लोगों को सीधे अयोध्या के लिए बस से वंचित होना पड़ रहा है।*

एआईसीटीएसएल अधिकारियों की मानें तो दिसंबर से अब तक करीब तीन बार टेंडर जारी हो चुके हैं लेकिन ठेकेदारों ने इनमें रुचि नहीं दिखाई। बताया जा रहा है कि एआईसीटीएसएल पर ठेकेदारों का लाखों रुपया बकाया है इसके चलते हैं वे नए टेंडर लेने में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जिसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले टेंडर दिसंबर में जारी किए गए जिम किसी भी ठेकेदारी में या कहें ऑपरेटर ने रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद फरवरी और फिर मार्च में भी इंदौर से अयोध्या बस के लिए टेंडर जारी किए गए लेकिन तीनों बार किसी ठेकेदार ने इनमें रुचि नहीं दिखाई। इस कारण इंदौर से अयोध्या बस फिलहाल ठंडे बस्ते में जा चुकी है।

एआईसीटीएसएल की शर्तें भी चुभ रहीं आपरेटरों को

सूत्रों की माने तो एआईसीटीएसएल ने इंदौर अयोध्या बस को लेकर जो नियम और शर्तें लागू की है वह भी आपरेटरों को चुभ रही है। जो मुख्य बातें सामने आ रही है उसमें यह है कि एक शर्त के अनुसार आपरेटर को ही बस की समस्त राशि वहां करना है जो ऑपरेटर को रास नहीं आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इंदौर से अयोध्या तक के लंबे रोड पर वोल्वो बसें चलाई जाना है जिनमें काफी अधिक खर्च आता है। इस कारण भी ऑपरेटर टेंडर में इंटरेस्ट नहीं दिख रहे हैं।

लोगों को नहीं मिल पा रहा सीधा साधन

उधर एआईसीटीएसएल अधिकारियों की लापरवाही और है धमेटा के कारण शहर वासी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इंदौर से अयोध्या के लिए कोई सीधी बस या ट्रेन नहीं है। रेलवे अधिकारी बता रहे हैं कि सिर्फ एक ट्रेन है जो सीधे अयोध्या जाती है, जिसमें काफी संख्या में यात्री होने के कारण वेटिंग भी बढ़ रही है।

प्रक्रिया चल रही है...

इंदौर से अयोध्या डायरेक्ट बस के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। अभी टेंडर ओपनिंग की तारीख बाकी है। प्रक्रिया चल रही है जल्द ही बस सेवा शुरू हो सकेगी।

- मनोज पाठक, सीईओ,
एआईसीटीएसएल, इंदौर

यूजी और पीजी कोर्स में 1 में से होगा एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन

इंदौर। सरकारी और निजी कालेज से संचालित स्नातक-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। एक मई से स्नातक और दो मई से स्नातकोत्तर कोर्स में पंजीयन शुरू होंगे, जो 21 मई तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते है। इस बीच छात्र-छात्राओं को दस्तावेज का सत्यापन भी करवाना है। पसंदीदा कालेज व कोर्स की च्वाइंस भरने के बाद विद्यार्थियों को मई अंतिम सप्ताह में सीट आवंटित की जाएगी। सात दिन के भीतर विद्यार्थियों को फीस जमा करना है। अफसरों की मानें तो प्रदेशभर में यूजी की आठ और पीजी की 4 लाख सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

एक लाख सीटें कम-खरगोन में विश्वविद्यालय बनने से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले 80 कालेज शिफ्ट हो चुके हैं। इसके चलते करीब एक लाख दस हजार सीटें कम हो चुकी है। 160 कालेजों की यूजी में 1 लाख 90 हजार सीटें है, जबकि पीजी में सवा लाख सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। काउंसिलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को बीए, बीकाम, बीएससी, बीजेएमसी, बीएसडब्ल्यू, एमए, एमकाम, एमएससी सहित अन्य कोर्स शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश संबंधित कई नियमों में संशोधन किया है। इस बार से बीसीए में सभी संकाय में 12वीं करने वाले विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। साथ ही एलएलबी-एलएलएम जैसे कोर्स में पांच प्रतिशत अंक की छूट दी गई है।

दो चरण बाद सीएलसी-कालेजों की सीटें भरने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया रखी है। पहले दो चरण आनलाइन काउंसिलिंग की जाएगी, जबकि तीसरे चरण में कालेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) की जाएगी, जो 21 जून से शुरू होगा।

व्यक्तित्व विकास के लिए अंतरगुणों के साथ- साथ सच्चे ज्ञान को भी बढ़ाएं -डॉ.गीते

इंदौर। समाज सेवा प्रकोष्ठ द्वारा पिपलियाहाना क्षेत्र के कोठरी कॉलेज सभागार में 123 वाँ निशुल्क बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस वृहत शिविर में क्षेत्र की बस्तियों के लगभग दो सौ पचास बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। वरिष्ठ शिक्षाविद डा निहार गीते के मुख्य आतिथ्य तथा आई आई टी इंदौर के प्रो डा हेमचंद्र झा की विशेष उपस्थिति में पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र वितरण के साथ संपन्न हुआ। शिविर में योग, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य जागरूकता, बाल गोष्ठी तथा व्यक्तित्व विकास के विभिन्न विषयों में विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। वरिष्ठ शिक्षाविद डा निहार गीते ने समाज सेवा प्रकोष्ठ की गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सहभागियों को शिविर में दी गई जानकारी, ज्ञान और कलाओं को आत्मसात कर व्यक्तित्व का समग्र विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी भाषा और आचरण किसी भी व्यक्ति का पहला परिचय होता है। अतः इसे बेहतर बनाना चाहिए। ज्ञान और जानकारी में भी बहुत अंतर होता है। जानकारियां तो हर जगह उपलब्ध हो जाती है किंतु सही ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे शिविर ज्ञान की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डा हेमचंद्र झा ने कहा सफल व्यक्तित्व प्रायः सामान्य पृष्ठभूमि से ही आते हैं। अतः छोटे- छोटे संकल्पों को साधकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इससे पूर्व सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल की डा मोनिका डिसूजा ने शिविरार्थी बच्चों को संस्कृत का एक श्लोक समझाते हुए कहा कि विद्यार्थीजीवन में यदि पांच लक्षणों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्तित्व निर्माण की अच्छी नीव बनाई जा सकती है। एक विद्यार्थी में ये पांच लक्षण उपयोगी माने गए हैं, कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान लगाना, श्वान की तरह चौकन्नी नींद, आवश्यकतानुसार भोजन याने अल्पाहारी होना और विद्या अर्जन के लिए गृह त्यागने को भी तैयार रहना। सिस्टर जैकलीन ने भी बच्चों को खान- पान, स्वास्थ्य जागरूकता एवं नशे की आदतों से दूर रहने की सीख दी तथा प्रेरक गीत भी गवाए। प्रारंभ में ख्यात गायिका और संगीत गुरु सुश्री वर्षा झालानी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। संगीत में अलंकार, सुर, सरगम की जानकारी देते हुए इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत का गायन और अभ्यास कराया। योगाचार्य श्री बाला चैतन्य ने योगासन और कुछ हास्यासन कराए। वरिष्ठ चित्रकार व कलागुरु श्री राजेंद्र भाटिया ने चित्रकला के बारे में प्रशिक्षण दिया। तत्पश्चात आपके मार्गदर्शन में जल ही जीवन है तथा पर्यावरण संरक्षण विषयों पर बच्चों से चित्र बनवाकर प्रतियोगिता आयोजित की गई।श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

अतिथियों का स्वागत सर्वश्री आलोक खरे, संस्था सचिव श्री सुबोध भोरासकर, शिविर संयोजक प्रकाश गुप्ता,पुष्पा महादिक, सुमित्रा डिसूजा, माया ढोने,प्रकाश रावत आदि ने किया। इस अवसर पर सर्वश्री प्रकाश शर्मा, के एन रावल, दीपक गिरकर, सुरेश रायकवार, के के पांडेय, बी आर जाटव, अशोक सिसोदिया, लक्ष्मण पवार सहित क्षेत्र के अनेक गण्यमान्य नागरिक और कोठारी कॉलेज के शिक्षक गण भी उपस्थित रहे।सत्र संचालन श्री ब्रजेश कानूनगो ने तथा आभार प्रदर्शन श्री सुबोध भोरासकार ने किया।

मतदान प्रारंभ करने के डेढ़ घंटे पहले मॉक पोल होगा

इन्दौर। लोकसभा का चुनाव कराने नियुक्त मतदान दलों के पीठासीन अधिकारियों को अपने-अपने मतदान केन्द्र में वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के डेढ़ घंटे पहले मॉक पोल (दिखावटी मतदान) कराना होगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक मॉक पोल में कम से कम 50 मतों का होना चाहिए और इसे उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ताओं की मौजूदगी में कराना चाहिए। पीठासीन अधिकारी को मॉक पोल के परिणामों से मतदान अभिकर्ताओं को अवगत कराना होगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने के डेढ़ घंटे पूर्व मॉक पोल (दिखावटी मतदान) करायेंगे। मॉक पोल प्रारम्भ करते समय कम से कम दो अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्त्ता उपस्थित रहना चाहिये। यदि मॉक पोल के समय कोई भी मतदान अभिकर्त्ता उपस्थित न हो, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी अधिक से अधिक 15 मिनट मॉक पोल शुरू करने के लिये प्रतीक्षा कर सकता है, और यदि तब भी कोई मतदान अभिकर्त्ता नहीं आते हैं तो पीठासीन अधिकारी मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। मॉक पोल में यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान कोष्ठ में सभी अभ्यर्थियों के लिए मत डाले गये हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार मॉक पोल (दिखावटी मतदान) प्रारंभ करने के पहले ईव्हीएम की बैलेट यूनिट तथा वीपेट को मतदान प्रकोष्ठ में रखना होगा, जबकि ईव्हीएम की कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी अथवा उस मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा, जो बैलट यूनिट और व्हीव्हीपेट मशीन सही प्रकार से जोड़ने के बाद कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल करेगा। मॉक पोल में डाले गये मतों का अभिलेख पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी को रखना होगा। मॉक पोल की व्हीव्हीपेट की पर्चियों को भी इनके पीछे के भाग में मॉक पोल पर्ची की रबर सील लगानी होगी और इन पर्चियों को मोटे काले कागज के लिफाफे में रखकर पीठासीन अधिकारी की सील से मुहरबन्द और हस्ताक्षर कर सुरक्षित रखना होगा।

मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर निर्देश जारी

इन्दौर। मतदान केंद्र के 100 मी. के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किये हैं। निर्देशानुसार मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मी. के दायरे में केवल निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किये गये शासकीय सेवक ही मोबाइल फोन के उपयोग हेतु अधिकृत होंगे। आयोग के मुताबिक मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं दल के अन्य सदस्य को मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड़ में रखना होगा। वे केवल सेक्टर अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन प्रेक्षक से निर्वाचन सबंधी वार्तालाप अथवा अन्य अति आवश्यक परिस्थिति में मतदान केंद्र से बाहर निकलकर वार्तालाप के लिये मोबाईल फोन का उपयोग कर सकेंगे । बूथ लेवल ऑफिसर को वोटर असिस्टेंट बूथ पर तैनाती के दौरान ही अपने मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति होगी।

मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों से भरवाए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के फार्म

प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को मिलेगा नि:शुल्क इलाज - विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को भोपाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों का 5 लाख रूपए के निःशुल्क इलाज के लिए फार्म भरवाकर अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के शास्त्री नगर में 80 वर्षीय भंवरलाल पुरोहित, 74 वर्षीय श्रीमती भंवरीबाई पुरोहित, 82 वर्षीय श्रीमती पंकजा पी नायर और 82 वर्षीय श्रीमती मालती गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल के 6 नंबर स्टॉप के पास अंकुर कॉम्प्लेक्स में 84 वर्षीय कमलचंद कोठारी और 78 वर्षीय श्रीमती सरोज कोठारी के निवास पहुंचकर योजना का फार्म भरवाकर अभियान का शुभारंभ किया। शास्त्री नगर में योजना के शुभारंभ अवसर पर लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीष उपाध्याय उपस्थित रहे। योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुजुर्गों के लिए बड़ी योजना लाए हैं। इस योजना से देश के करीब 40 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी दी है। नरेन्द्र मोदी के ऐतिहासिक बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देशभर में बुजुर्गों को 5 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने लगेगी।

भारत में बुजुर्गों का ख्याल रखने की योजना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए इस योजना को लेकर आए हैं। पार्टी के संकल्प-पत्र में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को शामिल कर इसे पूरा करने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, ताकि 70 साल से अधिक आयु के हर वर्ग और हर समाज के बुजुर्गों को इलाज में कोई परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस योजना की खास बात यह है

इनकम टैक्स का दायरा इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इस योजना का लाभ हर 70 साल से अधिक बुजुर्ग को मिलेगा। 70 साल का हर बुजुर्ग 5 लाख का इलाज प्रदेश के किसी भी निजी अस्पताल में मुफ्त में करा सकेंगे। अगर इलाज में उसके बाद भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो प्रदेश सरकार ने एयर एंबुलेंस सुविधा को शुरू किया है। डॉक्टरों और कलेक्टर के आपस में संवाद के बाद उन्हें इस योजना का भी लाभ दिया जाएगा।

भाजपा का दृष्टिकोण हमेशा सेवा और समर्पण का रहा-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह चुनावी समय है, परन्तु भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण हमेशा सेवा और समर्पण का रहा है। हम बुजुर्गों की इस योजना को प्रदेश में सफलता के साथ पूरा कर हर पात्र बुजुर्ग को इसका लाभ दिलाएंगे। डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में 7 और 13 मई को होने वाले मतदान में बड़ी संख्या में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की जनता के आर्शीवाद से एक बार फिर मोदी सरकार और अबकी बार 400 पार होकर रहेगा। प्रदेश की सभी 29 सीटें भाजपा जीत कर नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर उनके हाथ मजबूत करेगी।

प्रधानमंत्री ने देशभर के बुजुर्गों को 5 लाख के निःशुल्क इलाज का अधिकार प्रदान किया

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर वर्ग व समाज के 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज का अधिकार प्रदान किया है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद नरेन्द्र मोदी ऐतिहासिक बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही यह योजना लागू हो जाएगी। देश के लाखों बुजुर्गों को अब समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा, कोई भी बुजुर्ग आर्थिक परेशानी की वजह से इलाज से वंचित नहीं रह सकेगा। प्रधानमंत्री ने इस योजना में आयकरदाताओं और गरीबी की रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को शामिल कर उनके इलाज की गारंटी दी है। इस योजना में किसी भी जाति, धर्म, समाज व क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के संकल्प पत्र में 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी दी थी। उसी के तहत आज से मध्यप्रदेश में बुजुर्गों के फार्म भरवाने की पक्रिया शुरू की गई है। मैं प्रदेशभर के बुजुर्गों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, जो सभी के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं।

शास्त्री नगर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अभियान की प्रदेश संयोजक श्रीमती सीमा सिंह जादौन, भाजपा के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी उपस्थित रहे। वहीं अंकुर काम्प्लेक्स में फार्म भरवाते समय पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, प्रदेश प्रवक्ता मिलन भार्गव, मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट सचिन वर्मा, श्रीमती वंदना त्रिपाठी व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा काम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज भोपाल के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा से आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत फॉर्म भराए जाएंगे और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का हिस्सा बनेंगे, ताकि बुजुर्गों को इसका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में जोड़कर बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत देश के गरीबों को चार करोड़ मकान दिए। उज्जवला योजना के तहत देशभर में महिलाओं को अब धुएं से राहत मिली है। साथ ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को लेकर सभी वर्गों का कल्याण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का डंका दुनिया में बज रहा है और देश पांचवी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत 2024 तक विश्व गुरू बनेगा और हमारा मध्यप्रदेश आने वाले पांच सालों में देश का नंबर एक राज्य बने इस दिशा में हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है।

पीएम मोदी ने शिवराज को लिखा पत्र कहा

यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं, कांग्रेस उद्देश्यों से वोटर्स को जागरूक करने की कही बात

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हरदा की सभा में पीएम मोदी ने शिवराज को अपना मित्र बताते हुए उन्हें दिल्ली ले जाने की बात कही थी। इसके बाद ये तय हो गया है कि शिवराज की भूमिका एमपी के बजाय दिल्ली में रहेगी। हरदा की सभा के बाद अब पीएम मोदी ने उन्हें पत्र लिखकर कृषि के क्षेत्र में किए गए कामों, नवाचारों की तारीफ करते हुए उन्हें कृषि के क्षेत्र में प्रेरणास्त्रोत बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव साधारण नहीं है। यह चुनाव हमारे वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का एक सुनहरा अवसर है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और उसके अलायंस के उदेश्यों को विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण बताते हुए मतदाताओं को जागरूक करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने लिखा छात्र राजनीति से ही आपकी संगठनात्मक क्षमताओं से लेकर चार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपका विशाल राजनीतिक अनुभव रहा है। आपके कार्यकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकल कर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। जिस प्रकार आपने राज्य में सकारात्मक विकास किया, महिलाओं, बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया।

तीन माह में भी नहीं हटाया जा सका बीआरटीएस कारिडोर

रोज परेशान हो रहे सैकड़ों लोग, अधूरे काम से लेन के बीच में फंस रहे हैं वाहन चालक

भोपाल। हलालपुर से संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) बाजार होते हुए सीहोर नाके तक बीआरटीएस कारिडोर हटाने का काम तीन माह बाद भी पूरा नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री डा। मोहन यादव ने एक माह में पूरा कारिडोर हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग अभी तक काम पूरा नहीं कर सका है। नतीजतन, वाहन चालकों और व्यापारियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने 20 जनवरी को हलालपुर बस स्टैंड के निकट से कारिडोर हटाने का काम प्रारंभ किया था। शुरूआत में काम तेजी से हुआ, लेकिन अब काम मंद गति से किया जा रहा है। अधूरे काम के कारण लोगों

को परेशान होना पड़ रहा है। बाजार में खरीदी करने आए लोगों को कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। मजबूरी में वे बंद पड़ी लेन के बीच में कार पार्क करते हैं तो यातायात पुलिस चालान बनाने लगती है। जबकिबंद हिस्से में ट्रैफिक भी बंद है।

योजनाबद्ध ढंग से नहीं हो रहा काम

पीडब्ल्यूडी का अमला योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं कर रहा है। इस कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लेन का एक हिस्सा खुला है, वहीं आगे जाकर वह संकरा हो जाता है। इसके चलते चार पहिया वाहन चालकों को वापस पीछे मुड़ना पड़ता है। कपड़ा संघ ने पहले इस अधूरे हिस्से को तोडने का आग्रह अधिकारियों से किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। कुछ जगह से यूनिपोल एवं सिग्नल भी नहीं हटाए गए हैं। रात के समय ये नजर नहीं आते, इससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। कपड़ा व्यापारी संघ के महासचिव दिनेश वाधवानी का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को प्लानिंग से काम करना चाहिए। पहले कारिडोर निर्माण के समय हमें परेशान होना पड़ा, अब हटाते समय भी वही परेशानी हो रही है।

कमलनाथ-दिग्गी से प्रचार नहीं कराना चाहते प्रत्याशी

मालवा-निमाड़ की सीटों के लिए जोश भरने आएंगे राहुल-प्रियंका

भोपाल। *कांग्रेस तीसरे और चौथे चरण में बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी कर रही है। मालवा और निमाड़ के लिए कांग्रेस के प्रदेश संगठन ने राहुल और प्रियंका गांधी की सभा मांगी है। वहीं कमलनाथ और दिग्विजयसिंह जैसे नेताओं की अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने डिमांड नहीं की है। इसके अलावा और भी कई स्टार प्रचारकों के नाम कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को भेजे थे, लेकिन उसमें से भी आधे भी चुनावी रण में नजर नहीं आ रहे हैं।*

फिलहाल कांग्रेस तीसरे चरण के चुनाव प्रचार की तैयारी में लगी है। यहां 9 मई को मतदान होना है। इसमें प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं बची हुई सीटों पर 13 मई को चुनाव होगा। प्रियंका गांधी इसके लिए मुरैना आ रही हैं, वहीं राहुल गांधी का दौरा अभी तक तय नहीं हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सभा कराने की तैयारी चल रही है। चौथा चरण जिसमें मालवा और

निमाड़ की सीटें शामिल हैं, यहां राहुल और प्रियंका की सभा की तैयारी की जा रही है। एक आमसभा प्रियंका गांधी की अदिवासी क्षेत्र में रखने की योजना है। राहुल गांधी मालवा की किसी सीट से आसपास की सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। वहीं प्रदेश में सचिन पायलट का नाम नए स्टार प्रचारक के रूप में सामने आया है। उनकी किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड है। प्रत्याशी चाह रहे हैं कि बड़े नेता उनके क्षेत्र में आए, जिसका लाभ उन्हें मिल सके, क्योंकि अंतिम समय में भाजपा भी चुनाव प्रचार में जोर लगाएगी। पिछली बार स्टार प्रचारक के रूप में कमलनाथ और दिग्विजसिंह की सभा की ज्यादा डिमांड थी, लेकिन इस बार वह नजर नहीं आ रही

है। कमलनाथ पहले दौर में छिंदवाड़ा से फ्री हो चुके हैं और दिग्विजयसिंह तीसरे चरण में अपने लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ से लगे हुए हैं। दोनों नेता फ्री हो जाएंगे, लेकिन उनकी ज्यादा डिमांड नहीं होने से कांग्रेस के बड़े नेता भी प्रत्याशियों पर दबाव नहीं बना रहे हैं।

स्टार प्रचारकों की फौज, लेकिन नहीं दिख रहा जोश

कहने को तो कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की फौज है, जिसमें कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। ये स्टार प्रचारक भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने में नाकाम ही नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तो शामिल हैं ही वहीं तीसरे नंबर पर कमलनाथ, चौथे पर दिग्विजयसिंह और पांचवें नंबर पर उमंग सिंघार हैं। इसके अलावा नकुलनाथ भी सूची में हैं, लेकिन उनकी भी डिमांड नहीं है। विवेक तनखा, अरूण यादव, कमलेश्वर पटेल, सज्जनसिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधो,जयवर्धनसिंह, शोभा ओझा, आरिफ मसूद जैसे नाम भी सूची में रखे गए हैं। क्षेत्रीय नेता होने के कारण ये अपने क्षेत्र तक ही सीमित हैं, इसलिए दूसरी लोकसभा में भी नहीं जा रहे हैं।

सोशल मीडिया के कारण व्यक्तिगत संपर्क से दूर

जब से पार्टी में सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ा है, उसने उन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निष्क्रिय-सा कर दिया है, जो पहले घर-घर जाकर लोगों से मिलते थे। कभी चाय तो कभी भोजन के बहाने वे अपने कार्यकर्ताओं के घर जाते थे और वहां आसपास के लोगों को बुलाकर सामाजिक संवाद होता था। अब हर जगह सोशल मीडिया है। अगर कोई सूचना भी देना हो या कार्यकर्ताओं से संपर्क करना हो तो मैसेज डाल दिया जाता है, लेकिन उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती।

भाजपा चली कांग्रेस की राह पर, इसलिए मतदान कम

बड़े नेता एसी रूम में बैठकर निर्देश दे देते हैं, नीचे काम हुआ या नहीं, इसकी परवाह कोई नहीं करता

भोपाल। प्रदेश भाजपा में कार्यकर्ताओं में जोश नहीं आना, नेताओं को निर्देश देकर उसकी समीक्षा नहीं करना, जनप्रतिनिधियों द्वारा दौरे नहीं करना और भी कई ऐसे बिंदु सामने आ रहा हैं, जिनके कारण प्रदेश में मतदान का प्रतिशत गिरा है। पार्टी विथ डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य मानने वाली भाजपा में समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी होती जा रही है।

प्रदेश की 12 सीटों पर हुए मतदान के कम प्रतिशत ने भाजपा नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसको लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मंथन शुरू हो गया है और आने वाले चरणों में ऐसी गड़बड़ी न हो, इसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश की ही स्थिति का आकलन किया जाए तो जिस तरह से पिछले साल भाजपा विपरित परिस्थितियों के बाद सत्ता में आई, उसने कार्यकर्ताओं की पूछपरख फिर कम कर दी। माना जा रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जब परिणाम आए तो वे अप्रत्याशित ही थे। एक बड़ा कारण यह भी है कि लगातार पांचवीं बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, जिससे बड़े नेता फीलगुड महसूस कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता वहीं का

वहीं खड़ा हुआ है। हालांकि भाजपा चुनावी कसरत पूरे समय करती रहती है, बावजूद उसके इस बार कम हुए मतदान ने बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है और ऊपर से गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान ने उन विधायकों और मंत्रियों को चिंता में डाल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कम मतदान हुआ तो मंत्री पद जाएगा।

बंद कमरे में बैठकर देते हैं निर्देश

आजकल भाजपा के नेता भी ऐसे हो गए हैं कि वे केवल बंद एसी कमरे में बैठकर निर्देश दे देते हैं। भाजपा ने चुनाव की व्यूह रचना को दूसरे क्षेत्र के नेताओं को सीटों का प्रभारी बनाकर भेजा है। यहां तक कि प्रभारी पर प्रभारी और संयोजकों की एक लंबी सूची है। प्रदेश और केन्द्र से निर्देश तो जारी हो जाते हैं, लेकिन उसका पालन निचले स्तर पर कितना हो रहा है, यह कोई नहीं देखता। हाल ही में लालवानी की नामांकन रैली में पार्षदों को भीड़ लाने के लिए कहा गया था, लेकिन पार्टी के 65 पार्षद, 8 विधायक, एक सांसद, एक जिला पंचायत अध्यक्ष मिलकर भी 6500 कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं कर पाए।

कार्यकर्ता के घर के बजाय होटलों में रहते हैं पदाधिकारी

भाजपा में जब संभागीय और जिला संगठन मंत्री का पद हुआ करता था तो ऐसे पदाधिकारी आरएसएस से आते थे। उनका मुख्यालय भाजपा कार्यालय हुआ करता था और कभी-कभी तो प्रवास के दौरान वे कार्यकर्ताओं के ही घर रूककर सामाजिक तानाबाना समझते थे। अब जो प्रभारी और संयोजक बनाए जाते हैं, वे होटलों में रुकते हैं, वहीं मीटिंग करते हैं। इस तरह से सामाजिक संपर्क लोगों से टूट जाता है।

कांग्रेस में है केडर का अभाव

कहने को भाजपा केडरबेस पार्टी है, लेकिन अब उसमें केडर स्तर पर ही सामंजस्य का अभाव देखा जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस चुनाव आने पर सक्रिय होती है, उसी तरह अब भाजपा का कार्यकर्ता चुनावी मोड में ही एक्टिव रहता है। वैसे संगठन की गतिविधि हमेशा एक तरह की चलने का दावा तो भाजपा में किया जाता है। लेकिन कुछ ज्यादा काम देने की वजह

विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल बोले-

कांग्रेस में रहकर क्षेत्र का विकास नहीं करा पाया; सीएम ने कहा-शिवपुर करेंगे श्योपुर का नाम

श्योपुर। श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी जॉइनिंग टोली के मुखिया नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। उनके साथ मुरैना नगर निगम की महापौर शारदा सोलंकी और करीब 2 हजार समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रावत ने कहा, हर किसी की इच्छा रहती है कि वह क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करे लेकिन जितना विकास मैं चाहता था, नहीं करा पाया। अब बीजेपी में शामिल होकर क्षेत्र को प्रदेश की मुख्यधारा तक ले जाना चाहता हूं। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, श्योपुर जिले का सही नाम शिवपुर है। बोलचाल में इसका नाम श्योपुर हो गया। आप चाहोगे तो विधानसभा में संशोधन करके इसका नाम शिवपुर कर देंगे। बाबा महाकाल का एक नाम शिव भी है। ऐसे नाम को सही रूप में लें तो आनंद आएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को श्योपुर जिले के विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा लेने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में रावत और सोलंकी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। विधानसभा सचिवालय को नहीं मिला इस्तीफा-रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव तय हो गया है। हालांकि, मंगलवार शाम तक विधानसभा सचिवालय को उनका इस्तीफा नहीं मिला था। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा, संभव है कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को उन्होंने इस्तीफा दिया हो और अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया हो। विधायक रावत ने पार्टी बदली है तो अब विजयपुर में उपचुनाव होना तय है।

विजयपुर से 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं-विधायक रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट से सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को टिकट दिए जाने से नाराज थे। वे अब तक विजयपुर से 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें भाजपा के पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा और सीताराम आदिवासी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। रावत कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। वे मुरैना-श्योपुर लोकसभा सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं।

Bollywood Update

अच्छी स्क्रिप्ट की

तलाश में हैं कैटरीना कैफ

कैटरीना कैफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जहां एक्ट्रेस ने अपने हॉलीवुड डेब्यू पर बात की है। कैटरीना कैफ ने हॉलीवुड जाने के प्लान के साथ ही बताया कि पहले वह एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी कर चुकी हैं। आइए, यहां जानते हैं आखिर कैटरीना कैफ अब हॉलीवुड जाना चाहती हैं या नहीं और उन्होंने किस वजह से प्रोजेक्ट ठुकरा दिया था? आपको बता दें कि कैटरीना कैफ अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए अक्सर लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं। कैटरीना कैफ ने साल 2003 में बूम से बॉलीवुड में कदम रखा था। बूम के बाद कैटरीना कैफ ने सलमान खान की रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया में काम किया था। इस फिल्म के बाद कैटरीना कैफ को खूब पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। मैंने प्यार क्यों किया के बाद कैटरीना कैफ के करियर में बैक-टू-बैक बिग बजट और हिट फिल्में आईं। जिनमें सिंह इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक था टाइगर, फितूर समेत कई फिल्में शामिल हैं। कैटरीना कैफ साल 2023 में सलमान खान के साथ टाइगर 3 में नजर आई थीं। एक्शन करने के बाद कैटरीना ने साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ फिल्म मैरी क्रिसमस में काम किया था। श्रीराम राघवन की फिल्म मैरी क्रिसमस भले बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन इसे क्रिटिक्स से बेहतरीन रिव्यू मिले थे। वहीं कैटरीना कैफ के नए प्रोजेक्ट्स पर अभी किसी तरह का अपडेट सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस फिलहाल अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में हैं।

जब आमिर के एक फैसले ने बदल दी इस एक्टर की जिंदगी

एक बार इंडस्ट्री में पैर जम जाए, तो फिर सारे संघर्ष सफल लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अभिनेता मुकेश ऋषि के साथ भी। घातक, सरफरोश फिल्मों के अभिनेता मुकेश ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान बताया कि कैसे 25 साल पहले फिल्म सरफरोश उन्हें मिली थी और वहां से करियर बदल गया था।

सरफरोश के मिलने की नहीं थी उम्मीद

मुकेश ने कहा कि शुरू में पता नहीं होता है कि कैसा काम मिलेगा। मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए आत्मविश्वास भी कम था कि कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। फिर काम करते-करते बहुत कुछ सीख लिया। उम्मीद नहीं थी कि सरफरोश जैसी फिल्म करियर के इतने शुरुआती दौर में मिल जाएगी। आमिर ने ही वह फिल्म मुझे

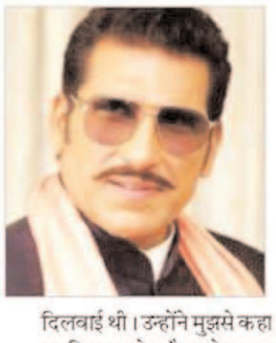

दिलवाई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक रोल है, मुझे लगता है कि तुम अच्छा कर लोगे, क्या करोगे। मैंने कहा- जरूर करूंगा। फिर पता चला कि मेकर्स मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं, मैंने वह टेस्ट भी दिया। सरफरोश का सफर जबरदस्त रहा। पहले मुझे अपनी पहली फिल्म गर्दिश में बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। वहां से सरफरोश फिल्म तक जब मैं पहुंचा, तो वहां से करियर में बदलाव आया।

श्रुति हासन का

ब्वॉयफ्रेंड शांतनु हजारिका संग टूटा सालों पुराना रिश्ता

श्रुति हासन ने साउथ से लेकर बॉलीवुज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। श्रुति अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि श्रुति की पर्सनल लाइफ में लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस का अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शांतनु हजारिका संग ब्रेकअप हो गया है। और अब इनके रास्ते अलग हो गए हैं। यहां तक कि दोनों ने सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। रिपोर्ट की मानें तो श्रुति और शांतनु कुछ पर्सनल इश्यू फेस कर रहे थे जिसके बाद इन्होंने ब्रेकअप करने का फैसला लिया। हालांकि दोनों ने इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं श्रुति ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, यह एक पागलपन भरी यात्रा रही, अपने बारे में और लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखना।

श्रुति और शांतनु लंबे समय से डेटिंग कर रहे थे

बता दें कि श्रुति और शांतनु लंबे समय से डेटिंग कर रहे थे और पिछले कुछ सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में भी थे। वे अक्सर एक साथ नजर आते थे और पब्लिकली भी एक-दूसरे के प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। श्रुति जहां एक्ट्रेस हैं तो वहीं शांतनु एक फेमस डूडल और मल्टीडिस्यलनरी विजुअल आर्टिस्ट हैं।

मॉर्डन दिखने के चक्कर में

ईशा गुप्ता हो गईं

ट्रोलर्स का शिकार

'आश्रम' फेम एक्ट्रेस ईशा गुप्ता अपनी बोल्डनेस से अक्सर इंटरनेट का पारा हाई रखती हैं। उनकी फिल्मों की तरह सोशल मीडिया से भी फैंस की नजरें नहीं हटती। जब भी ईशा तैयार होकर आती हैं फैंस के दिल घायल हो जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर वो अपनी अदाओं की बिजलियां गिराते हुए नजर आई हैं। अब हाल ही में एक फंक्शन में ईशा गुप्ता को देखा गया। इस दौरान एक्टर्स की ड्रेस देख सभी की आंखें फटी रह गईं।

ईशा गुप्ता हुईं बोल्ड

ईशा गुप्ता अब एक बेहद बोल्ड ड्रेस पहने हुए नजर आई हैं। एक्ट्रेस ने अवॉर्ड शो में शामिल होने के लिए एक ब्लैक सी थ्रू ड्रेस कैरी की। इस ड्रेस में वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड दिखीं और किसी के लिए भी उन्हें टक्कर दे पाना नामुमकिन हो गया। ईशा गुप्ता वैसे तो देखने में बेहद हॉट लग रही हैं लेकिन जब उनका ये वीडियो इंटनेट पर वायरल हुआ तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपने पहनावे के लिए बुरी

तरह ट्रोल हो रही हैं। यूजर्स एक्ट्रेस के कपड़ों को देख भद्दे-भद्दे कमेंट कर रहे हैं। साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति भी याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग इसे देखने के बाद अपना माथा पीट रहे हैं।'

बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आप भी ऐसे पा सकते हैं सरकारी नौकरी

देश में हजारों युवा हर साल सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए काफी तैयारी करते हैं, चाहे वह राज्य सरकार की नौकरी के लिए हो या केंद्र सरकार की नौकरी के लिए हो। लेकिन, इन परीक्षाओं को पास कर सरकारी नौकरी केवल गिने चुने उम्मीदवार ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षाओं के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें किसी परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होती है?

फायरमैन
रक्षा मंत्रालय में फायरमैन की नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए किसी परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है।

जी हां, आपने सही पढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये नौकरियां 300 से ज्यादा विभागों में उपलब्ध हैं, जिन्हें बिना लिखित परीक्षा के हासिल किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट, और राज्य सरकार के नौकरी पोर्टल पर जाकर उपलब्ध रिक्तियों पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा ऐसी नौकरियों के अवसरों के बारे में अधिक जानने के लिए, नीचे दी गई डिटेल पर एक आप एक नजर डालें।

मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नियमित रूप से सरकारी नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, जहां उम्मीदवार को कोई परीक्षा नहीं देनी होती है। कंटेंट राइटर, एडिटर और रिसर्चर के पदों पर उम्मीदवारों को बिना प्रवेश परीक्षा के नौकरी दी जाती है। सभी पदों के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता तय है।

आईआरसीटीसी
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन नियमित रूप से नौकरियों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित करता है। यहां फ्रेशर्स को बिना कोई परीक्षा दिए इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है। कुछ एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवारों को भी परीक्षा के साथ नौकरी मिल सकती है।

टाइपिस्ट
एक उम्मीदवार को बिना लिखित परीक्षा के भारतीय अदालत में टाइपिस्ट की नौकरी मिल सकती है। उन्हें बस एक इंटरव्यू और एक टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा।

संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, साइंटिस्ट-बी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड-I, स्पेशलिस्ट ग्रेड-III, इंजीनियर और कई अन्य पदों के लिए बिना एंट्रेंस टेस्ट नौकरियां प्रदान करता है।

भारतीय रेलवे, सेना और पब्लिक सेक्टर के बैंकों में नौकरियां
यहां असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर के पद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ये नौकरियां स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आती हैं।

12 वीं साइंस के बाद डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं तो ये हैं बेस्ट करियर ऑप्शन

हमारे देश में ज्यादातर युवा चाहते हैं कि वे डॉक्टर या इंजीनियर बनें लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो यह पेशा अपनाना नहीं चाहते हैं। अगर आपने भी 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की है और डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं तो आप किसी ऑफबीट कोर्स को कर सकते हैं। वर्तमान में कई ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं जिनमें आप 12वीं साइंस से उत्तीर्ण करने के बाद दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही आप कोर्स को खत्म करने के बाद इन क्षेत्रों में बेहतर करियर का निर्माण भी कर सकते हैं।

डाटा साइंटिस्ट
पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में डाटा साइंस साइंटिस्ट बेहद प्रचलन में है। आप पहले 12वीं के बाद गणित, सांख्यिकी या इंजीनियरिंग ग्रेड से बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप संबंधित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इससे रेलेटेड स्किल सीख सकते हैं। इसके बाद आप इसमें सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। एक बार डाटा साइंटिस्ट बनने के बाद आपको लाखों में वेतन प्राप्त कर हो सकता है।

साइंस टीचर
12वीं विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण करने के बाद आप टीचिंग से जुड़े डिग्री/ डिप्लोमा कर सकते हैं। इनको करने के बाद आप प्राइमरी टीचर लेवल से लेकर प्रोफेसर लेवल तक के टीचर बन सकते हैं। टीचिंग के क्षेत्र को सबसे बेहतर माना जाता है और इसमें बेहतर वेतन भी प्राप्त होता है।

आर्किटेक्ट
इनके अलावा अगर अपने पीसीएम विषयों के साथ इंटर उत्तीर्ण किया है तो आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। इस क्षेत्र में यूजी एवं पीजी दोनों ही प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। आप इनको करके आर्किटेक्चर के रूप में काम करके लाखों में वेतन पा सकते हैं।

GENERAL KNOWLEDGE

-**आखिर** विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश का है?
उत्तर- बता दें कि पूरे विश्व में सबसे कठोर कानून सऊदी अरब का है।
-क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में कौन सा फल सबसे ज्यादा खाया जाता है?
उत्तर- दरअसल, पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल केला है, क्योंकि यह हर सीजन में मिलता है।
- बताएं भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
उत्तर- भारत की सबसे चौड़ी नही ब्रहम्पुत्र नदी है।
-क्या आप बता सकते हैं कि आखिर विश्व में सबसे पहले कागज की करंसी जारी करने वाला देश कौन सा है?
उत्तर- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में सबसे पहले कागज की करंसी चीन द्वारा जारी की गई थी।

-एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है?
उत्तर- एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार बार धड़कता है।
-आखिर वो कौन सा देश है, जहां का हर नागरिक एक सैनिक के बराबर है?
उत्तर- बता दें कि इजराइल वो देश है, जहां का लगभग हर एक नागरिक एक सैनिक के बराबर है।
- क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत का अलीगढ़ शहर किस चीज के लिए मशहूर है?
उत्तर- आपको बता दें कि भारत का अलीगढ़ शहर तालों के लिए काफी मशहूर है।
- आखिर दुनिया में सबसे अधिक नापसंद की जाने वाली सब्जी कौन सी है?
उत्तर- दुनिया में सबसे अधिक नापसंद की जाने वाली सब्जी करेला है।
- क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है, जिसे हम खाते हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते?
उत्तर- बता दें कि कसम ऐसी चीज है, जो हम खाते तो हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते हैं।
- आखिर भारत के किस शहर में सास बहू मंदिर स्थित है?
उत्तर - दरअसल, राजस्थान के उदयपुर शहर में सास बहू मंदिर स्थित है।
- 1 दिन में कितने आलू खाने चाहिए?
उत्तर- दिन में एक बार आलू को सब्जी के रूप में या आलू के रस के रूप में खाया जा सकता है।
- आलू का नुकसान क्या है?
उत्तर- ज्यादा आलू खाने से वजन बढ़ सकता है या पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है।

इंदौर में शराब के अवैध परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही

हुंडई कार से देशी मदिरा प्लेन की 35 पेटी जप्त, दोनों की कीमत लगभग पौने 6 लाख

इन्दौर।इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन को देखते हुये शराब के अवैध क्रय/ विक्रय, परिवहन और भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देशन में आबकारी विभाग के अमले द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत एक वाहन से परिवहन की जा रही देशी शराब की 35 पेटी जप्त की गई। वाहन को भी जप्त कर लिया गया है। दोनों की कीमत लगभग पौने छ- लाख रुपये है। सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे ने बताया कि गत 27 अप्रैल 2024 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब लेकर आने पर सफेद कार हुंडई एक्सेंट एमएच-47-सी-8314 को पुराना एबी रोड बिजलपुर फाटे के सामने घेराबंदी कर पकड़ा गया। रोकने पर एक व्यक्ति उतरकर भागा। जिसे दौड़कर पकड़ लिया गया। जिसने अपना नाम दीनानाथ पिता हरेकृष्ण पाटीदार होना बताया। वाहन चालक ने अपना नाम मयंक पिता किशोर यादव होना बताया। कार की समक्ष पंचान तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट और डिक्की में 35 पेटियों में देशी मदिरा प्लेन की रखी पाई गयी। गते की पेटियों को

खोलकर चेक करने पर पेटियों में 1750 पाव के नग देशी मदिरा प्लेन थी। जो कि कुल 315 बल्क लीटर होना पाई गई। पकड़े गए वाहन का मूल्य 4 लाख 50 हजार रुपये है। शराब का मूल्य एक लाख 22 हजार 500 रुपये है। इस तरह वाहन व मदिरा का कुल मूल्य 5 लाख 72 हजार 500 रुपये बताया गया है।

36 और प्रकरण पंजीबद्ध-उल्लेखनीय है कि आबकारी की अलग-अलग टीमें दिन-रात अलग-अलग स्थानों पर सघन गश्त, भ्रमण और वाहन चेकिंग कर रही है। इस कार्यवाही को सम्मिलित करते हुए गत 27 अप्रैल 2024 को जिले के विभिन्न वृत्तों में की गयी कार्यवाहियों में कुल 36 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 1811 बल्क लीटर मदिरा, 910 किग्रा महुआ लहान, और 02 चार पहिया वाहन जप्त किये गए जिसकी सकल कीमत लगभग 20 लाख रुपये है। इसी कड़ी में 28 अप्रैल 2024 को वृत महू में आबकारी अमले द्वारा कार्यवाही करते हुए बड़गोदा स्थित ए-वन ढाबा से आरोपी संजय वर्मा के कब्जे से 31 बल्क लीटर बीयर और 2.25 बल्क लीटर शराब जप्त की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही जारी है।

मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को जिला अस्पताल में ड्यूटी देना होगी

स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग अब एक, डीन के अधिकार बढ़ेंगे

इन्दौर। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग एक हो गया है। जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से लिंक किया जा रहा है। इसलिए यहां के स्टाफ की सेवाएं अब जिला अस्पताल में भी ली जाएंगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के कुल बजट में से 30 प्रतिशत राशि को खर्च करने की अनुमति भी दी। कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों का बजट अगले महीने कार्यसमिति की बैठक में मंजूर किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल शनिवार को इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे वहां उन्होंने विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में जानकारी दी गई कि लांड्री, लैब सर्विस को आउटसोर्स किया जाएगा। डॉक्टरों को इन सभी कामों की जिम्मेदारी नहीं दी जाना चाहिए। उन्हें क्लीनिकल पार्ट पर ही ध्यान देना चाहिए। विभाग के प्रमुख सचिव ने बैठक में कहा कि आपको चाहिए उसका पूरा प्लान बनाकर दीजिए। यह सामान मिलने से हमें कितनी पीजी सीट अतिरिक्त मिलेंगी।

डीन के अधिकार बढ़ सकते है, ताकि उन्हें फाइलें लेकर बार-बार भोपाल की दौड़ नहीं लगाना पड़े। ज्वाइंट डायरेक्टर को एमवायएच का अधीक्षक बनाया जा सकता है। एमवायएच व अन्य अस्पतालों के तीन मैनेजरों की नियुक्ति भी हो सकती है। प्रमुख सचिव ने बताया कि कॉलेज से संबद्ध सभी अस्पतालों का बजट डीन के कंट्रोल में रहेगा। सभी अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारियों को एक जगह पर बैठकर काम करना चाहिए। सभी अस्पतालों का बजट अलग करने की बजाय एक ही बजट रखना चाहिए। उन्होंने चेताया कि छोटा-छोटा सामान भी खरीदो तो उसका भी टेंडर करें। छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान तो खुद ही कर करना चाहिए।

जिला भाजपा ने दिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश

इन्दौर। दो चरण के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत कम हुआ है उससे भाजपा चिंतित है। देश-प्रदेश के साथ इंदौर शहर और जिले में भी भाजपाई मतदान प्रतिशत बढ़े इसकी जुगत में लगे हैं। भाजपा कार्यालय पर जिला भाजपा अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कामकाजी बैठक के दौरान भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भाजपाई जुट जाए, शक्ति केन्द्र और बूथ स्तर पर मतदान कराने वाली टोलियां बनाएं। क्योंकि बूथ हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, बूथ जीतो चुनाव जीतो हमारा मंत्र है, बूथ जीतने के लिए हर बूथ पर कार्ययोजना बनाए, मतदान अधिक से अधिक हो इसके लिए टोलियां बनाकर उनसे काम करवाया जाए। सतीश मालवीय, प्रेमसिंह ढाबली, रामस्वरूप गे- हलोत, मुकेश चौहान, वरुण पाल, नवीन कुवादे, संदीप किरण सूर्यवंशी, मुकेश पटेल, राहुल चौहान, निलेश मंडलोई, दीपक राठौर, पंकज मीणा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत 11 मई को, आपसी समझौतों से विवादों का किया जायेगा निराकरण

इन्दौर। प्रदेश के इंदौर सहित जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ में नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 मई, 2024 को आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कम्पाउण्डेबल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जायेगा, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ लंबित मामलों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, धन वसूली संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित मामले, श्रम एवं रोजगार विवादों से संबंधित मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा मामलों से संबंधित प्रकरणों के साथ राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण के प्रयास भी किये जायेंगे।

इंदौर में आकार लेगा 321 बेड का कैंसर अस्पताल

इन्दौर। लंबे समय से अटक रहे नए कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य आखिर शुरू हो गया है। इससे अब मरीजों को नई बिल्डिंग के साथ ही आधुनिक मशीनों की सुविधाएं मिलने लगेगी। वर्तमान में जिस बिल्डिंग में अस्पताल संचालित हो रहा है वह काफी पुरानी है। साथ ही यहां लगी मशीनें भी बार-बार खराब हो जाती है। यहां अभी जमीन की सफाई के साथ ही मिट्टी परीक्षण आदि काम शुरू हो गया है

321 बेड का होगा अस्पताल

बता दें कि नया कैंसर अस्पताल ग्राउंड के साथ ही पांच मंजिल का होगा, जिसमें कुल 321 बेड होंगे। इसमें लीनियर एक्सेलरेटर के लिए दो बंकर, एक एचडीआर ब्रेकीथेरेपी मशीन और रेडियोथेरेपी समर्पित सीटी मशीन होगी। अत्याधुनिक तकनीक अस्पताल में डायग्नोस्टिक सुविधा और अनुसंधान प्रयोगशालाएं भी होंगी। अस्पताल में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी। इस अस्पताल के लिए 45 करोड़ की राशि पूर्व में ही स्वीकृत हो चुकी है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)